



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 350]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 30, 2008/आश्विन 8, 1930

No. 350]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 30, 2008/ASVINA 8, 1930

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरुआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2008

विषय : बेलारूस के मूल के अथवा वहां से निर्यातित नाइलॉन टायर कॉर्ड फैब्रिक्स के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत।

सं. 14/9/2008-डीजीएडी.—घरेलू उद्योग की ओर से एसोसिएशन ऑफ सिन्थेटिक फाइबर इण्डस्ट्री ने 1995 में यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 एवं सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित-वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतदपश्चात् नियमावली कहा गया है) के अनुसरण में बेलारूस (जिसे एतदपश्चात् संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित नाइलॉन टायर कॉर्ड फैब्रिक्स (एनटीसीएफ) (जिसे एतदपश्चात् संबद्ध वस्तु कहा गया है) के कथित पाटन के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने हेतु निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतदपश्चात् प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है।

और यतः प्राधिकारी ने यह देखा है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति और पाटन व क्षति के बीच कारणात्मक संबंध का प्रथमदृष्टया साक्ष्य मौजूद है, अतः प्राधिकारी उक्त नियमावली के नियम 5 के अनुसरण में कथित पाटन के अस्तित्व, सीमा तथा प्रभाव का निर्धारण करने और पाटनरोधी शुल्क की वह राशि संस्तुत करने, जिसे लगाए जाने पर वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी, उक्त नियमावली के नियम 5 के अनुसरण में कथित पाटन, एवं परिणामतः घरेलू उद्योग को हुई क्षति की एतद्वारा जांच शुरू करते हैं।

घरेलू उद्योग

2. घरेलू उत्पादकों, मैसर्स एसआरएफ लिमिटेड और मैसर्स सेंचुरी एंका लिमिटेड की ओर से एसोसिएशन ऑफ सिन्थेटिक फाइबर इण्डस्ट्री ने आवेदन प्रस्तुत किया है। ये दोनों कम्पनियां प्राधिकारकर्ता एसोसिएशन की सहभागी कम्पनियां हैं। मैसर्स एनआरसी लिमिटेड द्वारा भी संबद्ध वस्तु का उत्पादन किया जा रहा था, परंतु अब उन्होंने उत्पादन स्थागित कर दिया है। उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) तथा नियम 5(3)(क) के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से सहभागी कम्पनियों को पाटनरोधी जांच हेतु मामला दायर करने का अधिकार है।

विचाराधीन उत्पाद:-

3. विचाराधीन उत्पाद नायलॉन टायर कॉर्ड फैब्रिक (एनटीसीएफ) है जो अधिकांशतः टायर कॉर्ड के लिए अभिप्रेत होता है। एनटीसीएफ का अनुप्रयोग विभिन्न प्रकार के ऑटोमोटिव टायरों में होता है। नायलॉन टायर कॉर्ड फैब्रिक्स का उत्पादन कैप्रोलैक्टम से किया जाता है। नायलॉन चिप्स प्राप्त करने के लिए कैप्रोलैक्टम का प्रसंस्करण किया जाता है। तत्पश्चात् चिप्स का प्रसंस्करण करके यार्न प्राप्त किया जाता है। आगे यार्न के प्रसंस्करण से फैब्रिक प्राप्त किया जाता है। एनटीसीएफ का उत्पादन कई डेनियर्स में किया जाता है। एनटीसीएफ का प्रयोग टायरों के पुनर्नवीकरण के लिए किया जाता है। उत्पाद की बिक्री “ग्रे फैब्रिक” या “डिप्ड फैब्रिक” के रूप में की जाती है। अंततः उसकी खपत केवल डिप्ड रूप में होती है। उन मामलों में जहाँ उत्पाद की खरीद ग्रे रूप में की जाती है, क्रेताओं द्वारा उसकी डिपिंग की जाती है। सभी प्रकार के नायलॉन टायर कॉर्ड फैब्रिक विचाराधीन उत्पाद के दायरे के भीतर आते हैं।

4. विचाराधीन उत्पाद को सीमाशुल्क टैरिफ अध्याय 59 में उपशीर्ष 59.02.10.00 के तहत वर्गीकृत किया गया है। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और जाँच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

समान वस्तु

5. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उनके द्वारा विनिर्मित और संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु में कोई विशेष अंतर नहीं है जिसका कीमत, उपयोग, गुणवत्ता आदि पर प्रभाव पड़ सकता हो। याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया है कि याचिकाकर्ता और बेलारूस के निर्यातकों के बीच उत्पादन प्रक्रिया में कोई वास्तविक अंतर नहीं है। भौतिक एवं रासायनिक/यांत्रिक गुणधर्मों, विनिर्माण प्रक्रिया तथा प्रौद्योगिकी जैसी विशेषताओं के रूप में भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित और आयातित एनटीसीएफ तुलनीय हैं। दोनों तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और उपभोक्ताओं ने दोनों का एक-दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया है। अतः वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित वस्तु को नियमों के अर्थ के भीतर संबद्ध देश से आयातित उत्पाद के समान वस्तु माना जा रहा है।

शामिल देश

6. वर्तमान जाँच में शामिल देश बेलारूस है।

सामान्य मूल्य

7. आवेदक ने प्रस्ताव किया है कि बेलारूस को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाए और सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमों के अनुबंध-1 के पैरा -7 के अनुसार किया जाए। आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार यह प्रदर्शित होता है कि एकमात्र उत्पादक/निर्यातक राज्य द्वारा नियंत्रित होता है, अतः कम्पनी बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा करने की हकदार नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया है कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले उपयुक्त देश के रूप में ताइवान या थाइलैंड पर विचार किया जाए और थाइलैंड या ताइवान में एनटीसीएफ की उत्पादन लागत (उचित लाभ को जोड़ने के बाद) पर सामान्य मूल्य के रूप में विचार किया जाए। आवेदकों ने कहा है कि वे अब तक बाजार अर्थव्यवस्था वाले ऐसे किसी तीसरे देश में कीमत का पता नहीं लगा सके हैं।

तदनुसार, भारत में उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया गया है जिसे बिक्री, सामान्य तथा प्रशासनिक व्ययों और लाभ को जोड़कर विधिवत समायोजित किया गया है।

निर्यात कीमत

8. आवेदक ने आईबीआईएस (अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सूचना सेवा) के आधार पर निर्यात कीमतों का निर्धारण किया है। उपलब्ध कीमतें सीआईएफ निर्यात कीमतें हैं। आवेदक द्वारा कुल निर्यात कीमत का निर्धारण समुद्र भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, अंतर्देशीय परिवहन, पत्तन प्रहस्तन तथा पत्तन प्रभारों और भुगतान शर्तों में अंतर आदि समायोजनों के विभिन्न घटकों को शामिल करने के बाद किया गया है ताकि कारखाना द्वार स्तर पर कुल निर्यात कीमत का आकलन किया जा सके।

पाटन मार्जिन

9. उपर्युक्त के आधार पर संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य, कुल निर्यात कीमत से बहुत अधिक है जो प्रथम दृष्ट्या इस बात का संकेत है कि संबद्ध देश से निर्यातकों द्वारा संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है।

क्षति तथा कारणात्मक संबंध

10. आवेदक ने कथित पाटन के परिणामस्वरूप पाटित आयातों की बढ़ी हुई मात्रा के कारण उनके बाजार हिस्से में आई गिरावट के परिणामस्वरूप कीमत कटौती, कम बिक्री तथा घरेलू उद्योग हेतु नियोजित पूँजी पर आय में कमी के रूप में हुई क्षति से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण आवेदकों को हुई वास्तविक क्षति के पर्याप्त प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य मौजूद हैं।

जाँच की अवधि

11. वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ जाँच की अवधि 1 अप्रैल, 2007 से 31 मार्च, 2008 है। तथापि क्षति की जाँच की अवधि में अप्रैल, 2004 - मार्च 2005, अप्रैल 2005 - मार्च 2006, अप्रैल 2006 - मार्च 2007 तथा जाँच अवधि (पीओआई) शामिल होगी।

12. सूचना प्रस्तुत करना:

संबद्ध देश के निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावास के जरिए सरकार, भारत में उक्त उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों एवं प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को निर्धारित प्रपत्र एवं ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने लिए अलग से लिखा जा रहा है। वर्तमान जाँच में भागीदारी करने के इच्छुक पक्ष निम्नलिखित को लिख सकते हैं :-

निर्दिष्ट प्राधिकारी,

पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय,

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग

कमरा नं. 240, उद्योग भवन

नई दिल्ली - 110011

13. समय सीमा:

वर्तमान जाँच से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई हेतु कोई अनुरोध लिखित में भेजा जाए जो प्राधिकारी के पास उपर्युक्त पते पर इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिन) से पूर्व पहुंच जाना चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त हुई सूचना अधूरी है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी उपर्युक्त नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

14. अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

नियम के अनुसार हितबद्ध पक्षों द्वारा प्राधिकारी को प्रस्तुत की गई किसी भी गोपनीय सूचना का अगोपनीय सार प्रस्तुत करना अपेक्षित है। यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्ष की राय में ऐसी सूचना का सारांश तैयार करना संभव न हो तो उसके कारण का एक विवरण उपलब्ध कराना अपेक्षित होता है।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

15. नियम 6(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्ष उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय अंश रखे हुए हैं।

16. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है या उचित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जाँच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिश कर सकते हैं।

आर. गोपालन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2008

Subject : Initiation of Anti-dumping investigations concerning imports of Nylon Tyre Cord Fabrics originating in or exported from Belarus.

No. 14/9/2008-DGAD.—Association of Synthetic Fiber Industry on behalf of Domestic Industry filed an application before the Designated Authority (herein after referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on dumped articles and for determination of injury) Rules, 1995 (herein after referred to as Rules) for initiation of anti dumping investigation concerning alleged dumping of Nylon Tyre Cord Fabrics (NTCF) (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from Belarus (hereinafter referred to as subject country).

AND WHEREAS, the Authority finds that sufficient prima facie evidence of dumping of subject goods by the subject countries, injury to the domestic industry and causal links between the dumping and injury exist, the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of the Rule 5 of the said Rules, to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty, which if levied would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

Domestic Industry

2. Application has been filed by Association of Synthetic Fibre Industry on behalf of domestic producers M/s SRF Ltd and M/s Century Enka Ltd. These two companies are participating companies of the petitioner Association. M/s NRC Ltd was also producing the subject goods; however, they have suspended production now. As per the evidence available participating companies have the standing to file the case for anti dumping investigation on behalf of domestic industry as per Rule 2(b) and Rule 5(3)(a) of Anti Dumping Rules.

Product under consideration

3. The product under consideration is Nylon Tyre Cord Fabric (NTCF) which is meant largely for tyre cord. NTCF finds application in different kinds of automotive tyres. Nylon Tyre Cord Fabrics is produced from Caprolactam. Caprolactam is processed to obtain nylon chips. The chips are processed further to obtain yarn. Yarn is processed further to obtain fabric. NTCF is produced in a number of deniers. NTCF is used for the reinforcement of tyres. The product is sold as "Grey fabric" or "Dipped fabric". It is eventually consumed only in dipped form. In those cases where the product is purchased in grey form, dipping is done by the purchasers. All types of nylon tyre cord fabrics are within the scope of the product under consideration.

4. The product under consideration is classified under Customs Tariff Chapter 59 at sub-heading 59.02.10.00. The Custom classification is indicative only and not binding on the scope of investigation.

Like Articles

5. The Petitioner has claimed that there is no significant difference between the products manufactured by them and the subject goods imported from the subject country which can have any impact on price, usage, quality etc. The petitioner also claimed that there is no material difference in the production process between the petitioner and exporters from Belarus. The NTCF produced by Indian Industry and the one imported are comparable in terms of characteristics, such as, physical and chemical/mechanical characteristics, manufacturing process & technology. The two are chemically and commercially substitutable and consumers have used the two

interchangeably. Therefore, for the purpose of present investigation, the goods produced by the petitioner are to be treated as Like Articles of the product imported from the subject country within the meaning of the Rules.

Countries involved

6. The country involved in the present investigation is Belarus.

Normal value

7. The applicant have proposed that Belarus to be treated as Non Market Economy and the normal value is to be determined in terms of Para 7 of Annex-I of Anti Dumping Rules. As per the information provided by the applicants, it shows that the sole producer/exporter is state-controlled; the Company is, therefore, not entitled to claim Market Economic Treatment. They have suggested Taiwan or Thailand to be considered as an appropriate market economy third country and cost of production of NTCF in Thailand or Taiwan (after addition of reasonable profits) may be considered as normal value. The applicants have stated that as of now, they have not been able to procure the prices in such Market Economy Third Country. Accordingly, the Normal Value has been determined on the basis of cost of production in India, duly adjusted by including selling, general and administrative expenses and profit.

Export Price

8. The applicant has worked out the export prices based on IBIS (International Business Information Service). The prices available are CIF export prices. The net export price has been worked out by the applicant after adopting various elements of adjustments towards ocean freight, marine insurance, commission, inland transportation, port handling and port charges and difference in payment terms etc. to arrive at net export price at ex-factory level.

Dumping margin

9. Based on the above, the normal value of the subject goods in subject country comes out to significantly higher than the net export price prima-facie indicating that the subject goods are being dumped by the exporters from the subject country.

Injury and Causal Link

10. The applicant has furnished evidence regarding the injury having taken place as a result of the alleged dumping in the form of fall in their market share due to increased volume of dumped imports resulting in price undercutting, lost sales and decline in return on capital employed for the domestic industry. There is sufficient prima-facie evidence of the material injury being suffered by the applicants caused by dumped imports from subject country.

Period of investigation

11. The period of investigation for the purpose of present investigation is from 01st April 2007 to 31st March, 2008. The injury investigation period will however cover the periods April 2004–March 2005, April 2005–March 2006, April 2006–March 2007 and the Period of Investigation (POI).

Submission of information

12. The exporters in the subject country and their Government through their Embassy in India, importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all information relevant in the form and manner prescribed. The parties interested to participate in the present investigation may write to:

**The Designated Authority,
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties,
Ministry of Commerce & Industry,
Department of Commerce
Room No.240, Udyog Bhavan,
New Delhi-110107.**

Time limit

13. Any information relating to this investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the above address not later than 40 days from the date of publication of this notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record their findings on the basis of the facts available in accordance with the Rules supra.

Submission of Information on Non-Confidential basis

14. In terms of Rule 7, the interested parties are required to submit non-confidential summary of any confidential information provided to the Authority and if in the opinion of the party providing such information, such information is not susceptible to summarization, a statement of reason thereof, is required to be provided.

INSPECTION OF PUBLIC FILE

15. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

16. In case where an interested party refuses access to or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Governments as deemed fit.

R. GOPALAN, Designated Authority